विवरण -II

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं की सूची

अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (क) के तहत घोषित

1. खलियों व अन्य रातिबों सहित मवेशियों का चारा।
2. कोक और अन्य व्युतपन्नों सहित कोयला।
3. ओटोमोबाइल्स के संघटक भाग और पुर्जे।
4. सूती व ऊनी वस्त्र।
5. औषधियां।
6. खाद्य तिलहनों और तेलों सहित खाद्य पदार्थ।
7. लोहे और इस्पात के विनिर्मित उत्पादों समेत लोहा और इस्पात।
8. अखबारी कागज, पेपर बोर्ड और स्ट्रा बोर्ड सहित कागज।
9. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद।
10. कपास, ओटी हुई या बिना ओटी हुई तथा बिनौलें।
11. कच्चा पटसन।

अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखंड (XI) के तहत घोषित

12. जूट वस्त्र
13. उर्वरक, अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित
14. सीमेंट
15. वस्त्र उद्योग में काम आने वाली मशीनें:
    (i) बुनाई मशीन
    (ii) कताई मशीन
    (iii) लेस मेकिंग मशीन
    (iv) बिजली से चालित करघा (पावर लूम)
    (v) प्रसंस्करण में काम आने वाली मशीनें
16. रेशम निर्मित वस्त्र
17. सम्पूर्णत: या आंशिक रूप में मानव-निर्मित सेल्युलोसिक और नान-सेल्युलोसिक काते गए तन्तुओं से निर्मित वस्त्र।
18. सम्पूर्णत: या आंशक: मानव-निर्मित सेल्युलोसिक और नॉन सेल्युलोसिक फिलामेंट यार्न से निर्मित वस्त्र
19. सामान्य लाइटिंग सर्विस लैंम्प
20. बिजली की इस्त्री, हीटर और इसी प्रकार के अन्य उपकरणें जैसे घरेलू उपकरण
21. नारियल की भूसी (कच्चे या सडाए हुए)
22. बिजली के केबल और तार
23. मानव-निर्मित सेल्युलोसिक और नॉन-सेल्युलोसिक स्टैपल फाइबर
24. पूर्णत: या अंशत: निम्न में से किसी वस्तु से निर्मित यार्न:-

    (i) कपास (ii) ऊन (iii) मानव निर्मित सेल्युलोसिक कते हुए रेशें (iv) मानव निर्मित नॉन-सेल्युलोसिक कता हुआ रेखा (v) रेशम

25. (i) मानव निर्मित सेल्युलोसिक एंव नॉन सेल्युलोसिक फिलामेंट यार्न (ii) नाइलॉन टायर/कोर्ड/फैब्रिक
26. कापियां
27. नारियल की भूसी से निष्कर्षित क्वायर फाइबर
28. कीट नाशक, कवकनाशक, खर-पतवार नाशक और उन पैसे अन्य पदार्थ
29. चाय
30. (i) खाद्य फसलों के बीच और फलों व सब्जियों के बीज (ii) मवेशी चारों के बीच और (iii) पटसन बीज
31. (i) घरेलू व इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए स्विच (ii) 2-एम्पीयर स्विच (iii) 3-पिन प्लग और सॉकेट आउट लेट

Import of Onion

649. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the total quantity of onion which was proposed to be imported from the foreign countries and how much quantity has since been imported; and

(b) how much expenditure has since been incurred in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE' MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) The Government has accorded permission to import a quantity of 10,000 MTs of onion on a need based basis, on Government account, for distribution through public distribution agencies. Out of this, a quantity of 687 MTs were imported by NAFED for distribution in Delhi.

(b) As per the information furnished by NAFED a total expenditure of Rs. 1.61 crores was involved for the import of onions so far.

Attracting investment for upgrading facilities in foodgrains storage

650. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Government propose to adopt a policy to attract investment from domestic and foreign companies in upgrading facilities for storage and handling of foodgrains; and

(b) if so, the salient features of the policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) and (b) A steering Committee was constituted by the Government in the Deptt, of Food & Civil Supplies, M/o Food & Consumer Affairs to examine the question ofupgradation of technology particularly for bulk storage and bulk handling and transportation of foodgrains in India. The Committee has since submitted its report. The recommendations given by the Committe are under consideration of a Task Force set up for purpose.

Meeting of the Central Committee for Food Standard

651. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the meetings of the Central Committee for Food Standards constituted under the Act, are held regularly;

(b) what are the observations of the Committee regarding deficiencies in enforcement; and

(c) the proposed in this regard, if any?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) Yes Sir.

The Central Committee for Food Standards has observed on many occasions the deficiencies in enforcement of the P.FA. Act both at Centre and State level and suggested strengthening the infrastructure for effective implementation of the P.F.A. Act, 1954.

(c) (i) The Central Assistance is being given to States/UTs to strengthen their food testing labs. With equipments under a Centrally sponsored Scheme since 1990-91.

(ii) Equipments are also being supplied out of W.H.O. funds to State Food Labs.

(iii) The proposal to strengthen PFA Division in Directorate General of Health Services in the Ministry of Health & Family Welfare with fulfledged secretariat of C.C.F.S. has been processed.

(iv) Under the Public Health Capacity Building Project for seeking World Bank assistance a proposal for strengthening of PFA Infrastructure both at Central and State levels is being formulated.

(v) Orientation training to Food Inspectors, Public Analysts, Senior level officers and consumer Organisation organised from time to time.

एक आवश्यक वस्तु के तौर पर चाय

652. **श्री रामजीलाल :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 अगस्त, 1998 के "नवभारत टाइम्स" में चाय को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने की सिफारिश शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में 90 प्रतिशत से अधिक लोग चाय का प्रयोग करते हैं और इस आधार पर इसे आवश्यक वस्तुओं की सूची में डाला गया था; और

(घ) सरकार आम आदमी द्वारा प्रयोग की जाने वाली चाय की कीमतों पर किस प्रकार नियंत्रण करेगी ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां।